भारत में रोजगार की स्थिति – एक राजनीतिक वृत्तांत

अब असमानता के नकारात्मक परिणामों की बेहतर समझ बन चुकी है। साथ में इस बारे में भी बेहतर समझ बनी है कि किस तरह की आर्थिक संवृद्धि असमानताओं की ओर ले जाती हैं। विश्व भर में किए गए हाल के अनुसंधान से यह सामने आया है कि निरंतरता से बनी हुई अधिक असमानता दीर्घ–कालीन आर्थिक संवृद्धि को कम करती हैं। इसका एक पक्ष यह है कि असमानता निर्धन लोगों के लिए शिक्षा के अवसर कम करती है, इस कारण मानवीय पूंजी का गुणात्मक और संख्यात्मक प्रसार दब जाता है व तकनीकी विशेष कुशलताओं का प्रयास भी बाधित होता है। विषमता का किसी निर्धन व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है व इस कारण उसकी उत्पादकता कम हो सकती है। इस तरह भी आर्थिक संवृद्धि कम हो सकती है। विषमता पर पर्याप्त ध्यान देने से ही अब नीतियों का विमर्श 'समावेशी संवृद्धि' की ओर बढ़ा है।

अर्थव्यवस्था में रोजगार विहीन संवृद्धि की स्थिति में असमानता का अध्ययन और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर जब जिन रोजगारों का सृजन हो रहा है वह भी मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में हो रहा है या संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार के रूप में हो रहा है। यह स्थिति विशेषकर परेशान करने वाली है क्योंकि यह आर्थिक संवृद्धि की एक लुभावनी तस्वीर सामने रखती है जबकि साथ ही जनसंख्या के बड़े हिस्से की सामाजिक–आर्थिक प्रगति के अवसर अवरुद्ध हो रहे हैं। भारत एक निर्धन देश है व वह भी सामाजिक सुरक्षा कवच से वंचित। इसके करोड़ों नागरिकों के लिए कुछ न कुछ रोजगार तो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शायद इस कारण बेरोजगारी के आंकड़े अपेक्षाकृत कम नजर आते हैं।

क्या आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी?

अधिसंख्य भारतीयों के लिए अब चुनौती गुजर–बसर की नहीं है अपितु आकांक्षाओं की भी है। श्रम व रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 कहती है, "रोजगार सभी के दैनिक जीवन का हिस्सा है व किसी भी व्यक्ति की गरिमा, सही रहन–सहन व मनुष्य के रूप में विकास के लिए अति महत्त्वपूर्ण है।" इस तरह सरकार की सोच में भी अच्छे, सम्मानजनक, 'डीसेंट' रोजगारों के माध्यम से गरिमा प्राप्त करने की बात है, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग है व ऐसे दृश्यों में नजर आती है जैसे कि सफाईकर्मी के कार्य के लिए किसी इंजीनियर का आवेदन करना। आकांक्षा प्रेरित भारतीयों के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि कोई भी रोजगार मिल जाए, उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अच्छा, डीसेंट रोजगार चाहिए, पर इस तरह का रोजगार मिलना बहुत कठिन हो रहा है। किसी भी तरह का रोजगार मजबूरी में स्वीकार कर लेना व ऐसा रोजगार प्राप्त करना जो आकांक्षाओं व योग्यताओं के अनुकूल हो यह दो स्थितियां बहुत अलग हैं; पर भारत में तो फिलहाल दोनों स्तरों पर विफलता नजर आ रही है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में स्वीकार किया गया, "भारत अपनी बढ़ती हुई श्रम शक्ति की आकांक्षाओं की पूर्त्ति के लिए बहुत कम रोजगारों का सृजन

कर पाता है, व इस कारण अनेक व्यक्ति कामगार शक्ति से बाहर रह जाते हैं, अनेकों को अर्द्ध या अल्प रोजगार मिलता है व अनेक को बहुत कम मजदूरी या आय मिलती है।"

हालांकि भारतीयों को रोजगार मिल तो रहे हैं, पर प्रायः वे ऐसे बुरे या अरुचिकर रोजगारों में फंसे हुए हैं जिसमें वेतन बहुत कम है, या ऐसे रोजगारों में है जो उनकी शैक्षिक योग्यता से कम की श्रेणी के हैं, या ऐसे रोजगारों में किसी तरह आ गए हैं जिसके अनुकूल उनके पास क्षमताएं नहीं हैं। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में चपरासियों व संदेशवाहकों के 62 पदों के लिए 93000 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया जिनमें से 3700 पीएचडी थे, 28000 स्नातकोत्तर थे व 50000 स्नातक थे। इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता पांचवी कक्षा पास होना रखी गई थी। (इकनामिक टाईम्स 2018) उद्योग इसे अल्प–रोजगार कहता है। (दास 2019)

अच्छे रोजगारों की कमी व आय की बढ़ती विषमता भारत में रोजगार बाजार की असमानता के दो महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं।

बड़े वायदे, छोटी वृद्धि

वर्ष 2014 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार सृजन करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया जिसे अनेक युवा मतदाताओं ने आकर्षित किया जो शायद स्वयं भी रोजगार ढूंढ रहे थे। पांच वर्ष बाद यह लक्ष्य प्राप्ति से बहुत दूर हैं। विश्व बैंक के अनुसार, पहले जैसे रोजगार को बनाए रखने के लिए भारत में एक वर्ष में 80 लाख रोजगारों का सृजन होना चाहिए (दास 2019)। वर्ष 2004–05 और 2011–12 के बीच भारत ने गैर–कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 75 लाख रोजगारों का सृजन किया। 2011–12 और 2015–16 के बीच सरकार प्रति वर्ष मात्र 22 लाख रोजगारों का सृजन कर सकी। (मेहरोत्रा 2019)

मोहनदास पाई (पूर्व बोर्ड सदस्य, इन्फोसिस) ने कहा है कि एक वर्ष में 170 लाख भारतवासी रोजगार खोजते हैं जिनमें से 100 लाख (1 करोड़) को उचित मजदूरी व योग्यता का रोजगार नहीं मिलता है। 10 वर्षों में इनकी संख्या 10 करोड़ हो जाती है। 21 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में ऐसे अच्छे रोजगार प्राप्त न होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 करोड़ है। (दास 2019 में उद्धरण)

बढ़ती हुई बेरोजगारी

नवीनतम अप्रकाशित श्रम ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार (सरकार ने अधिकृत तौर पर अभी इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया है), वर्ष 2017–18 में बेरोजगारी चार दशकों के अधिकतम स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के बाद के चार वर्षों में यह उच्चतम स्तर पर पहुंची है (झा 2019ए)। महेश व्यास (2018ए), सेंटर फार मानिटरिंग ऑफ इंडियन इकनामी (सी.एम. आई.ई.) के अनुसार विमुद्रीकरण से पहले श्रम–भागेदारी 47 प्रतिशत थी पर विमुद्रीकरण के बाद अगस्त 2018 में यह 42.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसका अर्थ यह है कि लगभग 4 प्रतिशत रोजगार की आयु की जनसंख्या विमुद्रीकरण के बाद श्रम–शक्ति से बाहर हो गई। इनमें से अधिकांश महिलाएं थीं। महिलाओं का श्रम–शक्ति में भागेदारी का कम होना एक गंभीर समस्या है।

मेहरोत्रा (2019) के अनुसार भारत में विकास के इस चरण में अर्थव्यवस्था को कृषि की अपेक्षा गैर–कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन करना चाहिए। मेहरोत्रा का अनुमान है कि 2004–05 से 2011–12 के बीच 512 लाख गैर–कृषि रोजगारों का सृजन हुआ (73 लाख प्रति वर्ष), किन्तु वर्ष 2012 के बाद प्रति वर्ष मात्र 12 लाख रोजगारों का सृजन हुआ। वर्ष 2015–16 तक कुल 48 लाख रोजगारों का सृजन हुआ व वर्ष 2017–18 तक और 35 लाख के सृजन होने की उम्मीद है। वर्ष

2011–12 और वर्ष 2015–16 के बीच औद्योगिक (मैनुफैक्चरिंग) क्षेत्र से 106 लाख रोजगार मिट गए।

कामगारों के लिए रोजगारों की घटती गुणवत्ता

उदारीकरण आरंभ होने के बाद के दौर में अधिकतर रोजगारों का सृजन सेवा (सर्विस) क्षेत्र में हुआ। पर यह पर्याप्त नहीं रहा। औद्योगिक (मैनुफैक्चरिंग) व सेवा क्षेत्र में बढ़ते मशीनीकरण का अर्थ यह है कि अनेक रोजगार लुप्त हो रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटिड में एक अरब डालर के निवेश से दस लाख टन स्टील बनाने का संयंत्र लगा है पर इसमें मात्र 5000 कामगरों को रोजगार मिलता है। 5 वर्ष पहले इतने बड़े संयंत्र में 9000 कामगरों को रोजगार मिलता। (दास 2019)

अर्थव्यवस्था अपर्याप्त रोजगार सृजन व कम गुणवत्ता के रोजगारों की दो समस्याओं से जूझ रही है। इस कारण ऐसे लोगों की निर्धनता बढ़ रही है जो रोजगार तो कर रहे हैं पर जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट विश्व रोजगार सामाजिक आऊटलुक – ट्रेन्डस (2018) के अनुसार जहां कुछ सूचना, संचार व तकनीकी – सघन (आई.सी.टी.) सेवाओं में मजबूत रोजगार सृजन हुआ है, विशेषकर भारत में, पर सेवा क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में अधिकतर रोजगारों का सृजन पुरानी, कम मूल्य वृद्धि करने वाली सेवाओं में हुआ है, जहां अनौपचारिकता व असुरक्षित रोजगार अधिक हैं।

अनौपचारिकता की अधिकता के रोजगार प्राप्त कर रहे लोगों की गरीबी दूर होने की संभावनाएं कम हो जाती है – विशेषकर दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में। भारत, बांगलादेश, कंबोडिया व नेपाल जैसे देशों में अनौपचारिकता लगभग 90 प्रतिशत कामगरों को प्रभावित करती है। अनौपचारिकता की इतनी अधिक दर केवल कृषि तक ही सीमित नहीं है अपितु भारत जैसे देशों में यह निर्माण, व्यापार, आवास व खाद्य सेवा में भी व्यापक स्तर पर मौजूद है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आई.सी.टी. क्षेत्र में भारत में जिस रोजगार का सृजन हुआ वह अधिसंख्य तक नहीं पहुंच सका (रे 2015)। परम्परागत तौर पर अथिक श्रम–सघन क्षेत्र कपड़ा उद्योग, छोटे व मध्यम उद्यम रहे हैं। इन पर विभिन्न सरकारों ने समुचित ध्यान नहीं दिया जिससे पर्याप्त रोजगार सृजन भी यहां नहीं हो पाया। अन्य देशों से अधिक प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूल करेंसी स्थितियों का भी असर पड़ा। विमुद्रीकरण व जी.एस.टी. क्रियान्वयन का असंगठित क्षेत्र पर अधिक प्रतिकूल असर पड़ा (जेठमलानी 2018)। भारत में मैनुफैक्चरिंग उद्योगों में पहले औपचरिक क्षेत्र के सबसे अधिक रोजगार थे पर हाल के समय में इसमें भी अनौपचारिक रोजगार बढ़े हैं। यह कुछ हद तक श्रम बाजार की सख्तियों व गैर–लचीलेपन के कारण हुआ (मोरेनो–मोनोराय, पाईटर्स व एरुम्बेन 2012)।

रोजगार सृजन पर रोजगार–सुरक्षा नहीं

यह कोई अस्थाई स्थिति नहीं है अपितु व्यवस्थित तौर पर सरकारी नीति में बदलाव है। वर्ष 2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में निश्चित अवधि के अनुबंध के रोजगारों की नीति अपना रही है। इसका उद्देश्य अधिक तेजी से रोजगारों का सृजन बताया गया, पर इससे सरकारी नीति में रोजगार सुरक्षा से रोजगार सृजन की ओर बदलाव का संकेत मिला व इससे रोजगारों की गुणवत्ता उपेक्षित होती है। रोजगारों की गुणवत्ता में रोजगारों की दीर्घकालीन अवधि व सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इस समझ का कि जब तक

कोई विशेष नई परिस्थिति न हो रोजगार बना रहेगा व इसके साथ विभिन्न रूपों में सामाजिक सुरक्षा व अन्य लाभ जुड़े रहेंगे (जैसे बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि)। निश्चित अवधि के अनुबंधित रोजगार प्रायः कम समय के लिए होते हैं। सरकार की नई नीति आने से कंपनियां रोजगार सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा नकारने के तौर–तरीके खोज निकालेंगी। सरकार का प्रस्तावित औद्योगिक संबंधों पर श्रम कोड का प्रारूप श्रमिक संगठनों की शक्ति को बहुत कम करना चाहता है। रोजगार प्रदान करने वाले अपनी जरूरतों के अनुसार कामगारों को जब चाहें रख सकेंगे या हटा सकेंगे ऐसी स्थिति की ओर बढ़ा जा रहा है।

फलस्वरूप टिकाऊ रोजगारों व समावेशी श्रम बाजार नीतियों के सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद श्रम बाजार में बढ़ती असमानता ही नजर आई है (नन्दा 2018)। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान (एन.एस.एस.ओ.) के दो अंतिम रोजगार सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2004–05 और 2011–12 के बीच प्रति वर्ष स्थाई रोजगारों का सृजन लगभग 25 लाख था। वर्ष 2011–12 व 2016 के बीच स्थाई रोजगारों में नेट वार्षिक वृद्धि लगभग 15 लाख पर सिमट गई। इतना ही नहीं, ऐसे स्थाई कामगारों का हिस्सा श्रम–शक्ति में कम हुआ है जिनके पास प्राविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, बीमा आदि का सहारा है। लगभग आधे स्थाई मजदूरों को वर्ष 2004–05 में किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा उलब्ध थी। यह प्रतिशत 2011–12 में 45 हो गई व वर्ष 2016 में 38 हो गई। (राठौर व भट्टाचार्य 2018)

आंकड़े कुछ कहते हैं

एन.एस.एस.ओ. के अनुसार केवल एक तिहाई भारतीय मजदूरों के पास कोई लिखित अनुबंध है। 28 प्रतिशत मजदूर ही संगठित मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में है और उनमें से अनेक के रोजगार में सुरक्षा कम हुई है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 और 2013 के बीच संगठित मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र की कुल श्रम शक्ति में ठेके के मजदूरों का हिस्सा लगभग दोगुना हो गया है। अन्यत्र हमने बताया है कि किस तरह ठेके के कामगार एक स्थाई रोजगार वाले व्यक्ति से एक तिहाई से भी कम आय अर्जित करते हैं। इससे आय व कार्य की गुणवत्ता में असमानता उत्पन्न होती है। अब तो सरकारी सेवाओं में भी डाक्टरों, नर्सों, व अध्यापकों के अनुबंध की शर्तों पर कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

श्रम मंत्रालय के पांचवे वार्षिक रोजगार व बेरोजगारों के सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार 77 प्रतिशत भारतीय परिवारों में नियमित वेतन वाला एक भी सदस्य नहीं पाया गया।

अधिक संवृद्धि पर रोजगार नहीं

आर्थिक संवृद्धि की ऊंची दर के लंबे दौरों से गुजरने के बावजूद भारत में यह संवृद्धि रोजगार में वृद्धि में नहीं बदल पा रही है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया (एस.डबल्यू.आई 2018) रिपोर्ट ने हिसाब लगाया कि सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत वृद्धि पर रोजगार में 1 प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि युवाओं व शिक्षितों में बेरोजगारी की दर 16 प्रतिशत हो गई है। सरकार के गैर–प्रकाशित पीरियाडिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार युवाओं में बेरोजगारी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक स्तर पर है व पूर्ण जनसंख्या की बेरोजगारी दर से कहीं अधिक है। वर्ष 2011–12 में ग्रामीण युवाओं (15–29 वर्ष आयु) में बेरोजगारी 5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2017–18 में 17.4 प्रतिशत तक पहुंच गई। (झा 2019 बी)। जब रोजगार कम होते हैं व लोग अधिक तो उपलब्ध वेतनों में गिरावट आ जाती है। शिक्षित युवाओं को

अपेक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता है तो वे इसकी तलाश भी कम कर देते हैं। यह स्थिति देश की सामाजिक–राजनीतिक स्थितियों के लिए खतरनाक है।

श्रम बाजार का खंडीकरण जारी

एस. डबल्यू.आई. 2018 के अनुसार जहां सभी क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी है, जाति व लिंग आधारित विषमताएं अधिक बनी हुई हैं। मजदूरी की तुलना में श्रम उत्पादकता कई गुणा अधिक बढ़ी है। फलस्वरूप रोजगार प्रदान करने वालों को कामगारों की अपेक्षा आर्थिक संवृद्धि का कहीं अधिक लाभ मिला है। वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (2018) के अनुसार जहां विश्व स्तर पर मजदूरी की वृद्धि दर वर्ष 2017 में अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई, भारत में कामगारों की वास्तविक मजदूरी वृद्धि वर्ष 2008 व 2017 के बीच 5.5 प्रतिशत रही जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक थी। दूसरी ओर भारत में मजदूरी में लैंगिक भेद 34.5 प्रतिशत पाया गया जो 73 देशों में सबसे अधिक था। जहां वास्तविक मजदूरी निरंतरता से बढ़ रही है, फिर भी मासिक आय कम बनी हुई है – 82 प्रतिशत पुरुषों व 92 प्रतिशत महिलाओं की आय 10000 रुपए प्रति माह से कम है। पांचवे वार्षिक रोजगार व बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार 22 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 5000 रुपए से अधिक नहीं थी। चार सदस्यों का परिवार है तो इस आय से बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती हैं।

मजदूरी में असमानता से समग्र रूप में आय की असमानता बढ़ती है। भारत में श्रम उत्पादकता के अतिरिक्त अनेक अन्य कारण मजदूरी असमानता को प्रभावित करते हैं जैसे ठेके व स्थाई कर्मियों में मजदूरी में भेद, औपचारिक व गैर औपचारिक, कृषि व गैर कृषि क्षेत्रों में भेद व जाति, धर्म की पृष्ठभूमि आदि। (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन – आई एल ओ 2012)

एस.डबल्यू.आई. 2018 के अनुसार सभी सेवा क्षेत्रों में महिलाओं की 16 प्रतिशत स्थिति है पर केवल घरेलू कर्मियों को लें तो इनमें महिलाओं की 60 प्रतिशत उपस्थिति है। इसी तरह अनुसूचित जातियों के सभी कामगारों में 18.5 प्रतिशत उपस्थिति है पर केवल चमड़ा उद्योग कामगारों को देखें तो उनकी उपस्थिति 46 प्रतिशत है। इस उद्योग में कार्य की स्थितियां स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।

विकास मॉडल पर सवाल

क्या रोजगारों की घटती गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसी एक विशेष सरकार की है? क्या एक के बाद एक विभिन्न सरकारों ने कामगारों की निर्धनता, मजदूरी की विषमता, कार्य असुरक्षा व बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों की उपेक्षा की है? अथवा कोई ऐसे व्यापक सरंचनात्मक मुद्दे हैं जिनकी वजह से रोजगार कम हो रहे हैं व रोजगारों की गुणवत्ता भी गिर रही है।

हमें लगता है कि मौजूदा विकास के मॉडल ने देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न की है। रोजगार–सघन मध्यम, छोटे व सूक्ष्म उद्यमों को अधिक महत्त्व देने के स्थान पर पूंजी–सघन विशालकाय परियोजनाओं को महत्त्व दिया गया व इस कारण बेरोजगारी की समस्या गंभीर हुई। यह गुजरात में भी देखा गया जहां प्रवासी मजदूरों को स्थानीय लोगों ने 2018 में वापस भेजा। इससे यहां के विकास मॉडल के तनाव अभिव्यक्त होते हैं (लालीवाला व जेफरेलो 2018)।

20 लाख करोड़ रुपयों के निवेश पर हस्ताक्षर हुए, पर 10 प्रतिशत से कम निवेश वास्तव में हुआ। वास्तविक निवेश कम हुआ है, व इससे अधिक रोजगारों का सृजन भी नहीं हुआ। गुजरात सरकार के 2017–18 के सामाजिक–आर्थिक आकलन के अनुसार जनवरी 1983 और 31 जुलाई 2017 के बीच 2.75 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ जिससे 6251 परियोजनाओं में मात्र एक लाख

रोजगारों का सृजन हुआ। गुजरात मॉडल में रोजगार विहीन संवृद्धि का सृजन हो रहा है क्योंकि श्रम–सघन के स्थान पर पूंजी–सघन परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परंपरागत उद्यमी चेतना के स्थान पर याराना पूंजीवाद के आ जाने से बहुत अस्थिर स्थिति उत्पन्न हो गई है। (हैंसमैन 2014)।

एन.एस.एस.ओ. 73वें राऊंड (2015–16) के अनुसार गुजरात में मध्यम, छोटे व सूक्ष्म उद्यमों में 60 लाख लोगों का रोजगार है। इन उद्यमों विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों पर विमुद्रीकरण व बैंकों के संकट का प्रतिकूल असर पड़ा है। बैंक का संकट सहकारी बैंकों की गिरावट व एन.पी.ए. में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुआ।

इसके बावजूद गुजरात में औद्योगिक संवृद्धि ने इसे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश व बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए अधिक आकर्षक राज्य बनाया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 के अनुसार 20–29 आयु वर्ग में नेट प्रवास गुजरात में अधिकांश अन्य राज्यों में अधिक था। प्रवासी मजदूर अधिक घंटों तक कम मजदूरी पर कार्य करने को तैयार थे जिसका स्थानीय मजदूरों के रोजगार व आय की स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा (लालीवाला व जेफरेलोट 2018)।

बढ़ती बेरोजगारी व निराश युवा

युवाओं में रोजगार के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। यह चिंता अनेक युवा सर्वेक्षणों में सामने आई हैं। (बेनीवाल व प्रधान 2018)।

4675 व्यक्तियों में किए गए यूगव–मिंट मिलेनियल सर्वेक्षेण 2018 से यह सामने आया कि 18–21 आयु वर्ग में 72 प्रतिशत, 22–28 आयु वर्ग में 65.35 प्रतिशत, 29–37 आयु वर्ग में 52.4 प्रतिशत व 38–53 आयु वर्ग में 59.74 प्रतिशत ने कहा कि इन दिनों रोजगार प्राप्त करना कठिन है। 22–28 आयु वर्ग में डिप्लोमा/कालेज डिग्री या हाई स्कूल पास करने वालों ने बताया कि शहरी केन्द्रों में उनमें से अधिकतर 30000 रुपए प्रति माह से कम आय प्राप्त करते हैं जबकि उनकी अपेक्षा 30000 रुपए प्रति माह प्राप्त करने की है। (कवाटरा 2018)।

अधिक चिंताजनक यह है कि उन शिक्षित युवाओं (15–29 आयु वर्ग) की संख्या बढ़ रही है जो अब 'रोजगार, शिक्षा व प्रशिक्षण' किसी में नहीं हैं। इनकी संख्या वर्ष 2004–05 में 7 करोड़ थी, व वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक प्रति वर्ष 20 लाख की औसत से बढ़ती रही जबकि वर्ष 2011–12 व 2015–16 के बीच उनकी संख्या औसतन प्रति वर्ष 50 लाख की दर से बढ़ी। यदि यह प्रवृत्ति बनी रही तो मेहरोत्रा (2019) का अनुमान है कि वर्ष 2017–18 तक 11.5 करोड़ शिक्षित युवा श्रम–शक्ति से बाहर होंगे। इस तरह युवाओं के जनसंख्या में अधिक प्रतिशत से लाभान्वित होने के स्थान पर एक बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

शिक्षा में संकट

इस स्थिति के केन्द्र में भारतीय राज्य की अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने में विफलता है। ब्रिक देशों में भारत का शिक्षा पर खर्च सबसे कम है। इसका परिणाम है स्कूल की शिक्षा की निचले स्तर की गुणवत्ता व उचित शिक्षा ग्रहण न हो पाना।

हालांकि सरकार ने माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक (वोकेशनल) शिक्षा के विस्तार के लिए नए समग्र शिक्षा अभियान को आरंभ किया है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवों से पता चलता है कि रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो टीम के साथ मिलकर काम करने, समस्याएं

सुलझाने व अच्छे संप्रेषण में दक्ष हैं। केवल एक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त किए व्यक्ति का महत्त्व उनकी नजरों में अपेक्षाकृत कम है। आर.टी.ई कानून तो कक्षा 8 तक अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा के लिए बन गया है व इसे कक्षा 10 तक ले जाने की भी चर्चा है, पर अभी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत सुधार की जरूरत बनी हुई है।

कुशलता को बढ़ाने की जरूरत अभी बहुत बनी हुई है (विशेषकर श्रम–सघन क्षेत्रों में रोजगार की सफलता के लिए व बाहरी स्पर्धा में टिकने के लिए)। कपड़ा उद्योग में भारतीय कामगार की कार्य क्षमता बंगलादेश या श्रीलंका के कामगार की क्षमता से कहीं कम है। उत्पादकता में यह फर्क कुशलता की कमी के कारण है (दास 2019)। अतः इस कमी को दूर करने व कुशलता बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसमें अधिक निवेश की जरूरत है जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, संवृद्धि बढ़ेगी व अधिक रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

शिक्षा से रोजगार वृद्धि का पर्याप्त लाभ नहीं

भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे युवा है व उसकी मीडियन आयु 24 वर्ष है। वर्ष 2020 तक भारत की औसत आयु 29 होगी, जबकि चीन में यह 37 होगी व जापान में 48 होगी। (दास 2019)। इस समय भारत में सबसे अधिक युवा जनसंख्या है। भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या 15–59 आयु वर्ग यानि रोजगार सक्रियता के आयु वर्ग की है। इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी 2035–40 तक बढ़ने की संभावना है व इस कारण अपनी जनसंख्या के आयु वर्ग की स्थिति से लाभान्वित होने की सबसे अधिक संभावनाएं भारत के पास हैं (कपूर 2019)।

फिक्की नैसकाम की 'भारत में रोजगार का भविष्य' रिपोर्ट (2017) ने बताया है कि भूमंडलीकरण व अधिक युवाओं वाली जनसंख्या आगामी वर्षों में भारत के रोजगार की स्थिति को निर्धारित करेंगे। जनसंख्या से जुडी 'अवसरों की खिड़की' तब खुलती हुई मानी जाती है जब रोजगार के आयु वर्ग की (या कार्यशील) जनसंख्या की वृद्धि दर कुल जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक मानी जाती है। इससे अधिक आय, अधिक बचत, प्रति व्यक्ति अधिक पूंजी व अधिक संवृद्धि की उपलब्धि होती है जिसे जनसंख्या संबंधी लाभ या डिविडेंड कहा जाता है। (कपूर 2019)। पर यही स्थिति तब जोखिम भरी हो जाती है यदि अधिकांश युवाओं के पास उचित शिक्षा न हो या वे अपनी आकांक्षाओं के अनुकूल रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में न हों। प्रकाशित (व सरकार द्वारा अस्वीकृत) पी.एल.एफ.एस. 2017–18 के आंकड़े बताते हैं कि 15–29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर ग्रामीण पुरुषों में 17.4 प्रतिशत है व ग्रामीण महिलाओं में 13.6 प्रतिशत। इसी आयु वर्ग में शहरी पुरुषों में बेरोजगारी 18.7 प्रतिशत है व शहरी महिलाओं में 27.2 प्रतिशत है। अधिकतर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में हैं व वास्तविक आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं।

15–29 आयु वर्ग के 30 प्रतिशत से अधिक भारतीय न तो रोजगार में हैं न शिक्षा में न प्रशिक्षण में (ओ.ई.सी.डी. आर्थिक सर्वेक्षण : भारत, 2017)। इस स्थिति के कारण हैं – अच्छे व डीसेंट रोजगारों का उपलब्ध न हो पाना, कम गुणवत्ता की शिक्षा व अवसरों या प्रोत्साहन के अभाव में शिक्षा की ओर लौट कर न आ पाना।

श्रम ब्यूरो के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुमानों के आधार पर मेहरोत्रा (2019) ने बताया है कि देश में बेरोजगारी की वृद्धि में तेज वृद्धि हुई है। जो मिडल स्कूल पास हैं उनके लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2011–12 में 0.6 प्रतिशत थी यह 2016 में बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई। जो कक्षा 10 पास हैं उनके लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2011–12 में 1.3 प्रतिशत थी, वर्ष 2018 में यह बढ़ कर 3.2 प्रतिशत हो गई। इसी तरह कक्षा 12 पास की श्रेणी में इस दौरान बेरोजगारी दर 2 से 4.4 प्रतिशत बढ़ गई।

स्नातकों के लिए इस दौरान बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत से 8.4 प्रतिशत बढ़ गई। स्नातकोत्तर श्रेणी में यह दर 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। टेक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत तक पहुंच गई, स्नातकोत्तरों के लिए 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई व व्यवसायिक प्रशिक्षण की श्रेणी में 4.9 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत तक बढ़ गई इस तरह जितने अधिक शिक्षित हैं उतनी ही बेरोजगारी की संभावना बढ़ जाती है। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के रोजगार आवेदन कार्यालयों में 12.98 लाख बेरोजगार युवाओं के नाम दर्ज थे। इसका एक कारण यह है कि जो शिक्षित हैं वे निचले स्तर पर अनौपचारिक रोजगार करना नहीं चाहते हैं, पर दूसरी ओर स्थाई अपेक्षित वेतन का रोजगार उनके लिए उपलब्ध नहीं है। (वैराग्य 2018)। इस स्थिति में कुछ बहुचर्चित घोटाले हुए हैं (जैसे कि व्यापम)। (व्यापम घोटाला परीक्षा, प्रवेश व भरती घोटाला था जो मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में पर्दाफाश हुआ। इसमें अनेक भ्रष्ट नेता, कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकारी व व्यवसायी पर्दाफाश हुए जो परीक्षार्थी के स्थान पर किसी ओर से प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लिखवाते थे, परीक्षार्थियों की सीटों को बदलते थे व संबंधित अधिकारियों को रिश्वत देकर जाली उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाते थे।)

विषयों के चयन में लैंगिक स्तर पर भी विषमताएं हैं। छात्राओं को प्रायः कला व ह्यूमैनिटीज विषयों में भेजा जाता है व उनकी विज्ञान के विषय लेने की संभावना कम होती है। यूनेस्को (2017) के अनुसार मात्र 30 प्रतिशत छात्राएं विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग व गणित के विषय उच्च शिक्षा में लेती हैं। इस कारण वे अधिक वेतन वाले इन विषयों से जुड़े रोजगार प्राप्त नहीं कर सकती है। आजम व अन्य (2010) के अनुसार खुलकर या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से (अंग्रेजी न बोलने की तुलना में) पुरुषों में आय अर्जन की संभावना 34 प्रतिशत बढ़ जाती है।

केवल रोजगार नहीं, अच्छे रोजगार

कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर–कृषि रोजगार इसकी अपेक्षा कहीं कम सृजित हो रहे हैं जितने कि इस क्षेत्र के लिए संभावित कामगार उपलब्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वर्ष 2005 के बाद के समय से गैर –कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में ही रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। 2004–05 और 2011–12 के बीच जब भारत की 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 11.3 करोड़ से बढ़ी, उनमें छात्रों की संख्या 4.15 करोड़ से बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्र से युवा बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थानों में गए। इस तरह भविष्य में अच्छी गुणवत्ता के रोजगार अपेक्षित करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

दूसरा भारत

सोशल मीडिया व टेलीविजन में भारतीय समाज की आकांक्षा की सफलता की अनेक बड़ी व आकर्षक कहानियां हैं। हम अम्बानी और बड़े फिल्म सितारों की कहानियों में रुचि लेते हैं, रियलिटी शो देखते हैं जिनमें अचानक करोड़पति बन जाते हैं, मजदूरों या आटो रिक्शा चलाने वालों के बच्चों को आई.ए.एस. में चयनित होने के बारे में सुनते हैं। इस तरह माहौल बनता है कि ऊपर तक जाने के तमाम अवसर खुले हैं, कोई मेहनत करे तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। (हलर्नकर 2018)।

पर वास्तविकता इससे बहुत दूर है। याराना पूंजीवाद बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के अवसर प्राप्त कर या अन्य तरह से राज्य से विशेष सुविधाएं प्राप्त कर अरबपति बनने वाले भारत के अरबपतियों में 43 प्रतिशत हैं व उनके पास अरबपतियों की संपत्ति का 60

प्रतिशत हिस्सा है। (आक्सफैम 2018)। इस तरह आर्थिक दबदबे, सामाजिक पूंजी और शक्तिशाली तत्त्वों से सांठ–गांठ तेजी से ऊपर उठने के अधिक प्रचलित स्रोत हैं।

आकांक्षा का बहुत सा हिस्सा गुणवत्ता की शिक्षा न मिलने के कारण लुप्त हो जाता है, व एक छोटे अभिजात तबके को ही वैसी शिक्षा मिल पाती है जो आर्थिक व व्यवसायिक सफलता की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, 44514 स्कूलों में कक्षा 10 के 15 लाख बच्चों के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से पता चला कि राज्य शिक्षा बोर्डों से जुड़े छात्र (जो प्रायः अपेक्षाकृत निर्धन परिवारों से आते हैं) उपलब्धि में स्वतंत्र राष्ट्रीय बोर्डों के छात्रों (जो प्रायः अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों से आते हैं) से काफी पीछे रह जाते हैं। सार्वजनिक शिक्षा के अपने दायरे में भी गंभीर विषमताएं हैं। सरकारी सहयोग प्राप्त केन्द्रीय विद्यालय प्रति छात्र 27000 रुपए खर्च करते हैं जबकि अन्य सरकारी स्कूल प्रति छात्र 3000 रुपए खर्च करते हैं। शिक्षा के वार्षिक सर्वेक्षण (एसर) की रिपोर्टों में निजी व सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा स्तर गिरने की जानकारी मिलती है (हलर्नकर 2018)। इस तरह नई पीढ़ी में कुशलताओं, प्रशिक्षण व तैयारी के अभाव में मौजूदा हालात से ऊपर उठने की क्षमता सरकार द्वारा पर्याप्त निवेश के अभाव में अवरुद्ध हो रही है।

महिलाओं की गैर–मौजूदगी

पुरुषों की श्रम–शक्ति भागेदारी दर वर्ष 2015–16 में 75.5 प्रतिशत थी व 2016–17 में यह 76.8 प्रतिशत हो गई। महिलाओं के संदर्भ में यह वर्ष 2015–16 में 27.4 प्रतिशत थी व 2016–17 में घट कर 26.9 प्रतिशत हो गई (झा 2019ए)। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पुरुषों का श्रम–शक्ति में हिस्सा बढ़ रहा है, वहां महिलाएं विभिन्न कारणों से इसे छोड़ रही हैं – अच्छे रोजगारों के अभाव के कारण, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या महिलाओं के रोजगार के विरुद्ध प्रतिकूल सामाजिक मान्यताओं की वजह से।

महिलाएं चुपचाप सहती हैं

नीति आयोग के 2017–20 के एजेंडा में बताया गया है कि महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है, उन्हें कम उत्पादकता वाले रोजगार मिलते हैं व उन्हें देखरेख के गैर–भुगतान के कार्य अधिक मिलते हैं। श्रम–बाजार में महिलाओं का अवमूल्यन इस कारण होता है कि उनके अनुभव, शिक्षा व कुशलता को कम आंका जाता है। उन्हें अतिरिक्त श्रम के रूप में देखा जाता है व विमुद्रीकरण जैसे संकट की स्थिति में रोजगार से पहले उन्हीं को हटाया जाता है।

व्यास (2018 बी) ने विश्लेषण किया है कि महिलाओं को विमुद्रीकरण के बाद श्रम शक्ति से क्यों हटना पड़ा। वह बताते हैं कि सामान्य स्थितियों में भी महिलाओं के लिए रोजगार प्राप्त करना पुरुषों की अपेक्षा अधिक कठिन है। समाज में महिलाओं के रोजगार के विरुद्ध सोच है। विमुद्रीकरण के बाद उपलब्ध रोजगारों में कमी आई तो पुरुषों के लिए जगह बनी रहे इसके लिए महिलाओं ने पहले रोजगार छोड़ा। पहले से कम रोजगार उपलब्धि की स्थिति में अधिक अनुभवी पुरुषों के रोजगार बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई। इस तरह जब–जब अर्थव्यवस्था का बना–बनाया संतुलन टूटता है व रोजगार कम होते हैं तो पहले महिलाओं के रोजगार ही छिनते हैं।

विमुद्रीकरण के बाद उन परिवारों का प्रतिशत जिनमें दो या अधिक सदस्य रोजगार करते हैं, 34.8 प्रतिशत से कम होकर 31.8 प्रतिशत पर पहुंचा। इस स्थिति में महिलाओं ने रोजगार खोए।

महिलाएं परिवार की प्रतिष्ठा में व्यस्त

दूसरी ओर महिलाएं परिवार द्वारा आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने पर भी श्रम–शक्ति से बाहर हो जाती हैं। विश्व बैंक की 2017 की रिपोर्ट 'महिलाओं की भारत में श्रम–शक्ति में भागेदारी का पुनर्मूल्यांकन' में यह बताया गया है। इस रिपोर्ट में 2004–05 से 2011–12 तक के सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया गया है कि इस दौरान 96 लाख महिलाओं (रूमानिया की कुल जनसंख्या के बराबर) ने श्रम–शक्ति को छोड़ा। इनमें से 53 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं थीं (साहा 2017)।

केवल 27 प्रतिशत भारतीय महिलाएं श्रम–शक्ति में हैं। यह ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। जी–20 देशों में इस संदर्भ में केवल सऊदी अरब भारत से पीछे है (इंडिया स्पैंड 2016)।

श्रम–शक्ति में वे महिलाएं शामिल नहीं की जाती हैं जो गैर–भुगतान वाला देखरेख का कार्य करती हैं। यदि इस कार्य को शामिल किया जाए तो महिलाओं की भागेदारी पुरुषों से भी अधिक दर्ज होगी। घोष (2016) ने कार्य की व्यापक परिभाषा प्रस्तावित की है जिससे इसमें महिलाओं का गैर–भुगतान या देख–रेख का कार्य भी सम्मिलित हो व इस आधार पर उन्होंने बताया है कि श्रम–शक्ति में महिलाओं की भागेदारी निरंतरता से पुरुषों से अधिक रही है। वर्ष 2011–12 में, ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में, महिलाओं की कार्य भागेदारी दर 86.2 प्रतिशत पाई गई जो पुरुषों की कार्य भागेदारी (79.8 प्रतिशत) से कहीं अधिक थी। (घोष 2016)

विश्व बैंक (2017) के अध्ययन ने पाया कि महिलाओं का श्रम–भागेदारी का निर्णय सबसे अधिक घर में आर्थिक स्थिरता से प्रभावित होता है, न कि सामाजिक मान्यताओं, शिक्षा स्तर व आयु से। दूसरे शब्दों में, अधिक निर्धनता या आर्थिक तंगी की स्थिति में महिलाओं द्वारा रोजगार खोजने की संभावना अधिक है। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2004–05 और 2011–12 के बीच परिवारों में स्थाई आय अर्जित करने वालों का प्रतिशत बढ़ा जबकि स्व–रोजगार या अस्थाई रोजगार का प्रतिशत कम हुआ, जिसे परिवार में बढ़ती आर्थिक स्थिरता का द्योतक माना गया।

रोजगार छोड़ने के बाद महिलाओं की व्यस्तता ऐसे कार्यों में अधिक देखी गई जो परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित करने या बढ़ाने से जुड़े थे।

शिक्षा का सीमित उद्देश्य

अभिभावक अपनी बेटियों को शिक्षित करने को पहले से अधिक महत्त्व दे रहे हैं। सिंधु दिल्ली में घरेलू कर्मी है, पश्चिम बंगाल से आई है। उसके गांव में उसके बीमार पति व दो युवा बेटियां हैं। वह एक छोटे से कमरे में दो अन्य महिलाओं के साथ रहती है। वह एक परिवार में 12 घंटे काम करती है व फिर एक अन्य परिवार में कुछ अतिरिक्त आय के लिए पार्ट–टाईम काम भी करती है। वह कहती है – "मैं इस शहर में अपनी बेटी को पढ़ाने आई हूँ। वह बहुत होशियार है व प्राईवेट स्कूल में पढ़ती है। मैं उसके लिए व अपनी वृद्धावस्था के लिए यहां आई हूँ। (द वायर 2018)।

किन्तु माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से जरूरी नहीं कि महिलाओं की श्रम–शक्ति में भागेदारी हो जाएगी। महिलाओं की श्रम–शक्ति में भागेदारी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में कम है। यह शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक होने के कारण है। महिलाओं की श्रम–शक्ति में भागेदारी अनपढ़ वर्ग में या स्नातकों में अधिक है। पर इन दो समूहों में भी वर्ष 2004–05 व 2011–12 के बीच भागेदारी में गिरावट आई। साक्षरता आने से जरूरी नहीं है कि परिवार में महिला की निर्णय क्षमता या अधिकार बढ़ते हैं (इंडिया स्पैंड 2017)।

शिक्षा से पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित होना नहीं बढ़ रहा है (मजूमदार 2019)। राजस्थान में पिछले विधान–सभा चुनाव अभियान के समय उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा

राजे से बाड़मेर जिले की एक महिला ने सवाल पूछा – हम तुम्हें वोट क्यों दें जब हमारे शिक्षित बच्चे घर में बिना रोजगार के बैठे हैं (वशिष्ठ 2018 में उद्धित)।

लड़कियों की शिक्षा से प्रतिष्ठा बढ़ती है व विवाह में भी सहायता मिलती है, पर अधिक शिक्षा प्राप्त लड़कियों के रोजगार से दूर रहने का एक कारण यह है कि उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुकूल रोजगार उन्हें नहीं मिल रहे हैं (मजूमदार 2019)। फिर भी अभिभावक मानते हैं कि अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियों के लिए अध्यापक, नर्स, डाक्टर, सरकारी कर्मचारी जैसे सामाजिक मान्यता या प्रतिष्ठा प्राप्त रोजगार प्राप्त करने की अधिक संभावना है। पर ऐसे रोजगार न मिलने से यह संभावना बनी हुई है कि एक बार फिर लड़कियों को कम शिक्षा दिलवाने की प्रवृत्ति लौट सकती है।

निष्कर्ष व संस्तुतियां

यह स्पष्ट है कि भारत में रोजगार का एक बड़ा संकट है। इस संकट का उचित समय पर समाधान न हुआ तो इसका समाज की स्थिरता और शान्ति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। एक ओर जो दसियों लाख युवा श्रम–शक्ति में प्रतिवर्ष आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त रोजगार नहीं हैं व दूसरी ओर इन रोजगारों की गुणवत्ता व वेतन अपेक्षा से कहीं कम हैं। लिंग, जाति व धर्म आधारित भेदभावों के कारण भी अनेक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने में अतिरिक्त समस्याएं हैं। इस स्थिति से परेशान युवा एक समय के बाद रोजगार की तलाश छोड़ देते हैं। इन कारणों से सरकार द्वारा रोजगार प्राप्ति की सुविधाजनक परिभाषा के बावजूद बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक हो रहे हैं व यह प्रवृत्ति आगे और बढ़ सकती है। मौजूदा विकास मॉडल के आधार पर हमने अरबपतियों का अभिजात समुदाय बढ़ा दिया है व वर्ष 2017–18 में ऊपर के 1 प्रतिशत लोगों की संपत्ति 39 प्रतिशत बढ़ गई व नीचे के 50 प्रतिशत लोगों की संपत्ति मात्र 3 प्रतिशत बढ़ी (ग्लोबल वैल्थ रिपोर्ट)। 7.8 करोड़ संख्या तक बढ़ता हुआ मध्य–आय का समूह भी है पर उसका जनसंख्या में हिस्सा अभी कम ही है। (द इक्नामिस्ट 2018)। इस तरह जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में ऊपर उठने की आकांक्षा तो है पर अपनी मौजूदा कम वेतन व तंग आर्थिक स्थिति के चलते उठ पाने की उसकी क्षमता अभी बहुत कम है।

अतः सरकार को यह कदम उठाने होंगे

- विकास में प्राथमिकता श्रम–सघन क्षेत्रों को देनी चाहिए ताकि अधिक रोजगारों का सृजन हो।
- रोजगारों में वृद्धि समावेशी होनी चाहिए। नए रोजगारों में रोजगार सुरक्षा, बेहतर कार्य स्थितियां, सामाजिक सुरक्षा लाभ व संगठन बनाने का अधिकार उपलब्ध रहने चाहिए। इससे कुल उत्पादकता बढ़ेगी व इससे निवेश पर अधिक लाभ मिलेगा।
- स्वास्थ्य व शिक्षा में अधिक निवेश से उत्पादकता में सुधार होगा। यह दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भविष्य में बहुत रोजगार सृजन भी हो सकता है।
- कुशलता बढ़ाने पर बेहतर ध्यान देना चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिक सकें।
- सरकार को भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए। विषमता व बेरोजगारी बढ़ाने वाले अन्य कारकों जैसे याराना पूंजीवाद को नियंत्रित करना चाहिए। कर–नीतियां विषमता दर कम करने वाली होनी चाहिए। कारपोरेट टैक्स में छूट देने का अतिरिक्त उत्साह उचित नहीं है। इस तरह जो

अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा सुधारने के लिए करना चाहिए।

● ● ●

References:

Andres, Luis A., Basab Dasgupta, George Joseph, Vinoj Abraham and Maria Correia. (2017). Precarious Drop: Reassessing Patterns of Female Labor Force Participation in India. World Bank Policy Research Working Paper No. 8024. New Delhi: South Asia Region, Social Development Unit, Worl Bank. Available0 at: http://documents.worldbank.org/curated/en/559511491319990632/pdf/WPS8024.pdf - Accessed on 9 February 2019.

Azam, Mehtabul, Aimee Chin and Nishith Prakash. (2010). 'The Returns to English-Language Skills in India', IZA Discussion Paper No. 4802. Institute for Study of Labor (IZA). Bonn. Available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/35895/1/621224782.pdf - Accessed on 5 March 2019.

Basole, Amit, Arjun Jayadev, Anand Shrivastava and Rosa Abraham. (2018). State of Working India 2018. Bengaluru: Azim Premji University. Available at: https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/02/State_of_Working_India_2018-1.pdf - Accessed on 6 February 2019.

Bairagya, Indrajit. (2018). 'Why Is Unemployment Higher among the Educated?', Economic and Political Weekly, Vol. 53, Issue no. 7. 17 February 2018. Available at: https://www.epw.in/journal/2018/7/special-articles/why-unemployment-higher-among-educated.html - Accessed on 7 February 2019.

Beniwal, Vrishti and Bibhudatta Pradhan. (2018). 'Jobs please! What young voters want from politicians before 2019 polls', Business Standard, 19 September 2018. Available at: https://www.business-standard.com/article/politics/jobs-please-what-young-voters-want-from-politicians-before-2019-polls-118091900130_1.html - Accessed on 6 February 2019.

Das, Goutam. (2019). Jobonomics. India's Employment Crisis and What the Future Holds. Gurugram: Hatchett India.

Economic Times. (2018). 'Over 93,000 candidates, including 3,700 PhD holders apply for peon job in UP', Economic Times, 30 August 2018. Available at: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/over-93000-candidates-including-3700-phd-holders-apply-for-peon-job-in-up/articleshow/65604396.cms - Accessed on 5 March 2019.

Ernst & Young, NASSCOM and FICCI. (2017). Future of jobs in India. A 2022 perspective. Available online at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-future-of-jobs-in-india/%24FILE/ey-future-of-jobs-in-india.pdf - Accessed on 27 February 2019.

Garg, Lavanya. (2017). '65% Indian Women Literate. 5% Have Sole Control Over Choosing Their Husband', India Spend, 13 February 2017. Available at: https://archive.indiaspend.com/cover-story/65-indian-women-literate-5-have-sole-control-over-choosing-their-husband-71113 - Accessed on 9 February 2019.

Ghosh, Jayati. (2016). 'Time Poverty and The Poverty of Economics', METU Studies in Development, Vol, 43, No. 1 (2016). http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/879 - Accessed on 26 October 2018.

Halarnkar, Samar. (2018). 'A chasm between education and expectations leaves Indians unprepared for their country's realities', The Scroll, 3 June 2018. Available at: https://scroll.in/article/880627/a-chasm-between-education-and-expectations-leaves-indians-unprepared-for-their-countrys-realities - Accessed on 8 February 2019.

Hensman, Rohini. (2014). 'The Gujarat Model of Development: What would it do to the Indian Economy?', Economic and Political Weekly, Vol. 49, Issue No. 11, 15 March 2014. Available at: https://www.epw.in/node/129173/pdf - Accessed on 27 February 2019.

International Labour Organization. (2018). World Employment Social Outlook—Trends 2018. Geneva: ILO Office. Available at: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf - Accessed on 7 February 2019.

International Labour Organization. (2018). Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps. Geneva: ILO Office. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf -Accessed on 6 February 2019.

International Labour Organization. (2012). Global Wage Report 2012/13. Wages and Equitable Growth. Geneva: ILO Office. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_194843.pdf - Accessed on 5 March 2019.

Jha, Somesh. (2019a). 'Unemployment rate at four-decade high of 6.1% in 2017-18: NSSO survey', Business Standard, 6 February 2019. Available at: https://www.business-standard.com/article/economy-policy/unemployment-rate-at-five-decade-high-of-6-1-in-2017-18-nsso-survey-119013100053_1.html - Accessed on 6 February 2019.

Jha, Somesh. (2019b). 'Unemployment rose to a 4-year high during demonetisation: Govt. survey', Business Standard, 11 January 2019. Available at: https://www.business-standard.com/article/economy-policy/unemployment-peaked-to-4-year-high-during-demonetisation-govt-survey-119011001329_1.html - Accessed on 6 February 2019.

Kant, Amitabh, Vaibhav Kapoor and Ranveer Nagaich. (2018). 'India's burgeoning middle class', Live Mint, 23 January 2018. Available at: https://www.livemint.com/Opinion/TvcFydQcN6KEFkvdW7BprM/Indias-burgeoning-middle-class.html - Accessed on 5 March 2019.

Kapoor, Rashicka. (2019). 'Squandering India's demographic dividend', Business Standard, 14 February 2019. Available at: https://www.business-standard.com/article/opinion/squandering-india-s-demographic-dividend-119021401202_1.html?1550177234 – Accessed on 27 February 2019.

Kwatra, Nikita. (2018). 'Young India not so hopeful about job prospects', Live Mint, 3 September 2018. Available at: https://www.livemint.com/Industry/gw0jCKRG6dWpa4WkmYOQBN/Young-India-not-so-hopeful-about-job-prospects.html - Accessed on 6 February 2019.

Laliwala Sharik and Christophe Jaffrelot. (2018). 'A new Other', Indian Express, 22 October 2018. Available at: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/gujarat-model-development-rape-bihar-migrants-uttar-pradesh-labourers-alpesh-thakor-a-new-other-5411701/ - Accessed on 6 February 2019.

Majumdar, Shyamal. (2019). 'The job market paradox', Business Standard. 21 February 2019. Available at: https://www.business-standard.com/article/opinion/the-job-market-paradox-119022101175_1.html - Accessed on 27 February 2019.

Mehrotra, Santosh. (2019). 'India Does Have a Real Employment Crisis-And its Worsening', The Wire. 6 February 2019. Available at: https://thewire.in/economy/india-worsening-employment-crisis - Accessed on 6 February 2019.

Mehrotra, Santosh. (2018). 'The Indian Labour Market: A Fallacy, Two Looming Crises and a Tragedy', CSE Working Paper. Bengaluru: Azim Premji University. Available at: https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2018/05/Mehrotra_Labour_Market_Myth_Crises_Tragedy.pdf - Accessed on 27 February 2019.

Ministry of Labour & Employment. (n.d.). Fifth Annual Employment-Unemployment Survey 2015-16. Chandigarh: Ministry of Labour & Employment, Government of India.

Ministry of Labour & Employment. (2018). Annual Report 2017-18. New Delhi: Ministry of Labour & Employment, Government of India. Available at: https://labour.gov.in/sites/default/files/ANNUAL_REPORT_2017-18-ENGLISH.pdf - Accessed on 8 February 2019.

Ministry of Finance. (2017). Economic Survey of India 2016-17. New Delhi: Ministry of Finance, Department of EEconomic Affairs, Economic Division, Government of India. Available at: https://www.indiabudget.gov.in/es2016-17/echapter.pdf - Accessed on 28 February 2019.

Moreno-Monroy, A., J. Pieters, A. Erumban. (2012). Subcontracting and the size and composition of the informal sector: Evidence from Indian manufacturing. IZA Discussion Paper No. 6785. Bonn: Institute for the Study of Labor.

Nanda, Prashant K. (2018). 'Budget 2018 and Unemployment: Job creation comes in the spotlight', Live Mint, 2 February 2018. Available at: https://www.livemint.com/Politics/N2skEpg9vvHOjmV9S2TgTL/Budget-2018-and-Unemployment-Job-creation-comes-in-the-spot.html-Accessed on 7 February 2019.

NITI Aayog. (2017). India: Three Year Action Agenda. 2017-18 to 2019-20. New Delhi: NITI Aayog, Government of India. Available at: http://niti.gov.in/writereaddata/files/coop/India_ActionAgenda.pdf - Accessed on 28 February 2019.

OECD. (2017). OECD Economic Surveys. India: Overview. OECD. Available online at: https://www.oecd.org/eco/surveys/INDIA-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf - Accessed on 2 December 2018.

Oxfam India. (2018). India Inequality Report: Widening Gaps. New Delhi: Oxfam India.

Pande, Rohini, Jennifer Johnson and Eric Dodge. (2016). 'How to Get India's Women Working? First, Let Them Out of the House', India Spend, 9 April 2016. Available at: https://archive.indiaspend.com/cover-story/how-to-get-indias-women-working-first-let-them-out-of-the-house-74364 - Accessed on 9 February 2019.

Rathore, Udayan and Pramit Bhattacharya. (2018). 'The signal and noise in India's jobs data', Live Mint, 13 June 2018. Available at: https://www.livemint.com/Politics/BFASnfvkU1rxaGCYPYbIqN/The-signal-and-the-noise-in-Indias-jobs-data.html - Accessed on 7 February 2019.

Ray, A.S. (2015). 'The enigma of the "Indian Model" of development', in A. Calcagno, S. Dullien, A. Màrquez-Velázquez, N. Maystre and J. Priewe (eds), Rethinking development strategies after the financial crisis. Volume II: Country studies and international comparisons. Geneva and Berlin: UNCTAD and Fachhochschule fûr Technik und Wirtschaft.

Saha, Devanik. (2017). 'Rising Income Levels, Stability Linked to Declining Female Workforce Participation in India', India Spend, 4 May 2017. Available at: https://archive.indiaspend.com/cover-story/rising-income-levels-stability-linked-to-declining-female-workforce-participation-in-india-84594 - Accessed on 9 February 2019.

Sinha, Shalini. (2018). 'It's Time We Paid Women Workers Their Due', The Wire, 1 May 2018. Available at: https://thewire.in/labour/india-informal-workers-labour-may-day - Accessed on 9 February 2019.

Thomas, Jayan Jose. (2014). 'The Demographic Challenge and Employment Growth in India', Economic and Political Weekly, Vol. 49, Issue no. 6, 8 February 2014. Available at: https://www.epw.in/journal/2014/6/commentary/demographic-challenge-and-employment-growth-india.html - Accessed on 7 February 2019.

UNESCO. (2017). Women in Science. Fact Sheet No. 43, March 2017. UNESCO Institute for Statistics. Available at: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs43-women-in-science-2017-en.pdf - Accessed on 28 February 2019.

Vashishtha, Swati. (2018). 'Joblessness, Not Mon-Lynching, Is What Could Spell the End for BJP in Rajasthan', The Wire, 6 December 2018. Available at: https://thewire.in/politics/joblessness-not-mob-lynching-is-what-could-spell-the-end-for-bjp-in-rajasthan - Accessed on 5 March 2019.

Vyas, Mahesh. (2018a). 'September unemployment data show significant changes', Business Standard, 2 October 2018. Available at: https://www.business-standard.com/article/opinion/september-unemployment-data-show-significant-changes-118100100772_1.html - Accessed on 6 February 2019.

Vyas, Mahesh. (2018b). ‘Why lack of jobs does not lead to social strife’, Business Standard, 17 September 2018. Available at: https://www.business-standard.com/article/opinion/why-lack-of-jobs-does-not-lead-to-social-strife-118091700740_1.html -- Accessed on 6 February 2019. Rajasthan’, The Wire, 6 December 2018. Available at: https://thewire.in/politics/joblessness-not-mob-lynching-is-what-could-spell-the-end-for-bjp-in-rajasthan - Accessed on 5 March 2019.

Vyas, Mahesh. ¼2018a½. ‘September unemployment data show significant changes’, Business Standard, 2 October 2018. Available at: https://www.business-standard.com/article/opinion/september-unemployment-data-show-significant-changes-118100100772_1.html - Accessed on 6 February 2019.

Vyas, Mahesh. ¼2018b½. ‘Why lack of jobs does not lead to social strife’, Business Standard, 17 September 2018. Available at: https://www.business-standard.com/article/opinion/why-lack-of-jobs-does-not-lead-to-social-strife-118091700740_1.html -- Accessed on 6 February 2019.